V.V. NEWS

वर्ष-13
अंक-29
मूल्य-3
पृष्ठ-4
जौनपुर
18 जुलाई, 2022
सोमवार

सब पर नजर हर खबर पर नजर

वैशवारा

रा. हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/3924/2009
डाक पंजीयन जी आजमगढ़/एन.पी./119/15-16

दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लखनऊ, जौनपुर से एक साथ प्रकाशित

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से किया इनकार

– अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से किया इनकार

वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है।

यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया जवाब

यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है। यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ–साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने दलील देते हुए कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है।

देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 199 करोड़ से अधिक खुराक दी गई

देश में मंगलवार तक कोविड-19 रोधी टीकों की 199 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के मुताबिक, मंगलवार को शाम सात बजे तक नौ लाख से अधिक खुराक दी गई। देर रात अंतिम रिपोर्ट आने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।

नई दिल्ली। देश में मंगलवार तक कोविड–19 रोधी टीकों की 199 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के मुताबिक, मंगलवार को शाम सात बजे तक नौ लाख से अधिक खुराक दी गईं। देर रात अंतिम रिपोर्ट आने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को शाम सात बजे तक 18–59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कुल 99,752 एहतियाती खुराक दी गईं और अब तक इस आयु वर्ग में कुल 72, 83,051 एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 12–14 वर्ष आयु वर्ग के 3. 76 करोड़ बच्चों और 15–18 वर्ष के आयु वर्ग के 6.07 करोड़ किशोरों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश भर में पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीके दिए गए थे। दो फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू हुआ। अगले चरण का टीकाकरण अभियान एक मार्च 2021 को शुरू हुआ और इसके तहत 60 साल से अधिक आयु वाले और 45 तथा उससे अधिक उम्र के अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके दिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात

24 जुलाई को पूरा हो रहा है कोविंद का कार्यकाल

नई दिल्ली। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार चल रहा है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। इस पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। पीएम मोदी मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे और दोनों के बीच विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात का विस्तृत ब्योरा अभी नहीं मिला है।

राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 11 दिन बाद 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट कर सिर्फ इतना बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें, देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार चल रहा है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। इस पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से है।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे को दी श्रद्धांजलि

कहा- आज जो कुछ भी हूं उनके आशीर्वाद से हूं

मुंबई। आज गुरु पूर्णिमा है। सारा देश अपने गुरु के प्रति आस्था, समर्पण व आदर के भाव को प्रकट कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक का दौरा किया और शगुरु पूर्णिमाश के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनके जैसा आम आदमी बाल ठाकरे के आशीर्वाद से राज्य में शीर्ष पद ग्रहण कर सकता है। मेरी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई में बालासाहेब ठाकरे स्मारक पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए आज हम शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को नमन करने आए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उनके आशीर्वाद से और उनकी वजह से ही हूं। उनकी ये ही मंशा थी कि राज्य का विकास करें, सभी को न्याय मिले। सीएम ने यह भी कहा कि वह प्रशासन के संपर्क में हैं और राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। बाद में वह दिवंगत शिवसेना नेता और उनके गुरु आनंद दिघे को श्रद्धांजलि देने के लिए पड़ोसी ठाणे शहर गए। बता दें कि शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने पिछले महीने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

आषाढ़ की पूनम को ही क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय।
बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय।

जो व्यक्ति इतना महान हो तो उसके लिए भी एक दिन होता है, वह दिन है 'गुरु पूर्णिमा'। गुरु पूर्णिमा हिन्दू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु की आराधना का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था।

वेदव्यास को हम कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जानते है। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों और महाभारत की रचना की थी। हिन्दू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।

गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और मुडिया पूनो के नाम से जाना जाता है। यह एक पर्व है जिसे लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। यह संधिकाल होता है, क्योंकि इस समय के बाद से बारिश में तेजी आ जाती है। पुरातन काल में ऋषि, साधु, संत एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। चौमासा या बारिश के समय वे 4 माह के लिए किसी एक स्थान पर रुक जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा से 4 माह तक रुकते थे, यही कारण है कि इन्हीं 4 महीनों में प्रमुख व्रत त्योहार आते हैं।

गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग वेदव्यास की भक्तिभाव से आराधना व अपने मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। इस दिन हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बंगाल के साधु इस दिन सिर मुंडाकर परिक्रमा पर जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में इस पर्व को मुड़िया पूनो के नाम से मनाते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई इस दिन ब्रह्मा की पूजा करता है तो कोई अपने दीक्षा गुरु की। इस दिन लोग गुरु को साक्षात भगवान मानकर पूजन करते हैं।

इस दिन को मंदिरों, आश्रमों और गुरु की समाधियों पर धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह गुरुमय हो जाती है। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में धूनी वाले बाबा की समाधि पर यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश के साथ–साथ देश और विदेश से भी लोग आते हैं।

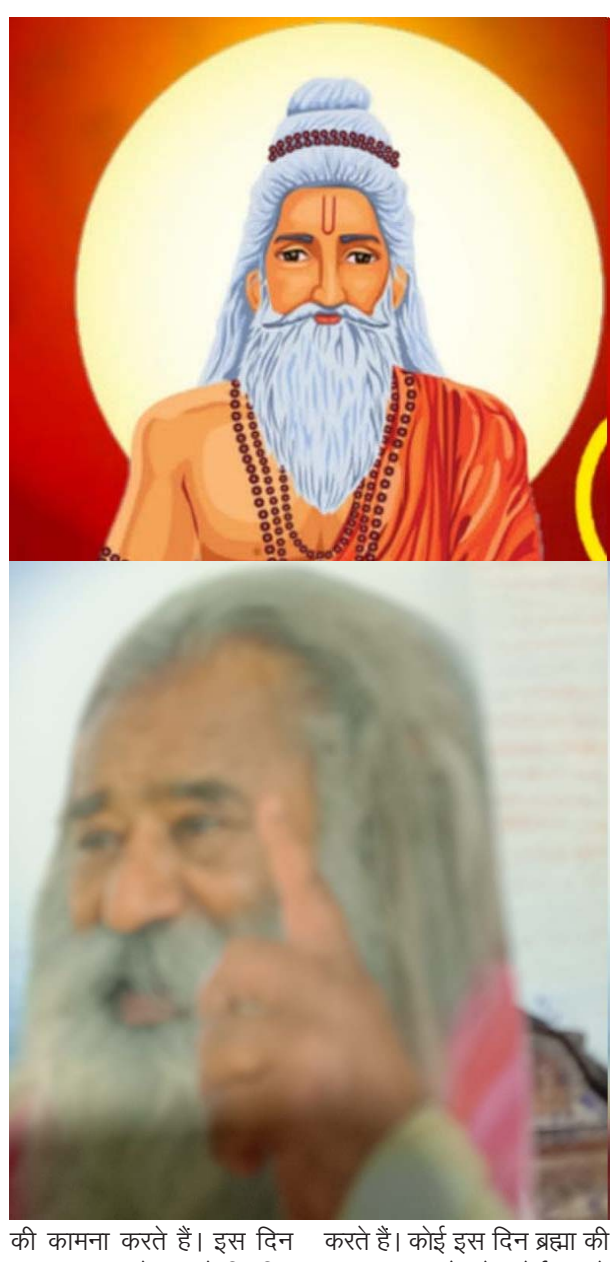

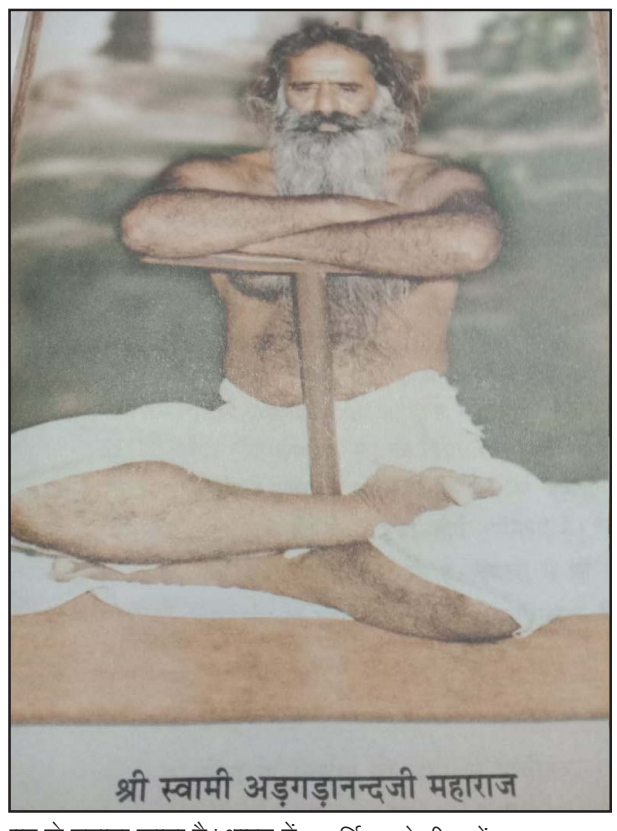

गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है? आषाढ़ की पूर्णिमा को यह पर्व मनाने का उद्देश्य है कि जब तेज बारिश के समय काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, तब गुरु उस चंद्र के समान है, जो काले बादलों के बीच से धरती को प्रकाशमान करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है कि तम का अंत करना या अंधेरे को खत्म करना!

अमरनाथ यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला

कहा- घर में घुसकर मारेंगे जैसा सलूक करने वालों का करना होगा मुकाबला

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह यात्रा (अमरनाथ यात्रा) हिंदू–मुस्लिम भाईचारे की निशानी होती थी लेकिन भाजपा ने इस यात्रा को सियासी हथकंडा बना दिया है कि जैसे जम्मू–कश्मीर को फतह करना है... इनके पास रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि एक दिन में यात्रा के लिए 5,000 से अधिक लोग नहीं जाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह समझते हैं कि जम्मू–कश्मीर किसी और का हिस्सा है और शघर में घुस कर मारेंगेश जैसा सलूक करते हैं। हमें इसका मुकाबला करना है। अगर हमने यह सोचा कि शजो हो गया, सो हो गयाश तो हमारा वजूद मिट जाएगा। हमारी जमीन, नौकरियां जा रही है। पीडीपी चीफ ने कहा कि हम एक मस्लिम बहुल प्रदेश हैं। हमने पाकिस्तान के साथ जाने से इंकार कर हिंदुस्तान से हाथ मिलाया। हमने इस मुल्क का झंडा कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों झंडों को सलाम करते रहे। लेकिन आज हमारे घरों में घुसकर झंडे लगाते हैं।

खिलाड़ियों ने कलर बेल्ट के लिये दिखाया जोश

जौनपुर। उत्तर प्रदेश ताइक्वाण्डो एसोसिएशन के तत्वावधान में जनपद के में जौनपुर ताइक्वाण्डो एसोसिएशन द्वारा कलर बेल्ट टेस्ट का आयोजन हुआ जहां येलो बेल्ट के लिये यश राय, सुमित राय, अनुराग यादव, सौरभ अग्रहरि, श्वेता प्रजापति, रूपचन्द वनवासी, लवलेश यादव, मोनू कन्नौजिया, विकास सोनकर, अर्जुन पाण्डेय और ब्लू बेल्ट के लिए आदित्य प्रताप सिंह, अनुपमा सिंह, श्रवण कुमार, निखिल राय, आदि ने दमखम दिखाया।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 18 जुलाई, 2022

सम्पादकीय.....

भयावह रूप लेता ध्वनि प्रदूषण

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा हाल में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट, 2022 के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है. यह भारतीय शहर दुनिया के उन शीर्ष आठ शहरों में शामिल है, जहां शोर का औसत स्तर 100 डेसिबल से ऊपर पहुंच चुका है. ढाका में दिन के समय शोर का स्तर 119 डेसिबल पहुंच जाता है, जबकि रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित मुरादाबाद में इसे 114 डेसिबल दर्ज किया गया है. इस सूची में कोलकाता और आसनसोल (89 डेसिबल), जयपुर (84 डेसिबल) और दिल्ली (83 डेसिबल) भी शामिल हैं, जहां ध्वनि आवृति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी है. गौरतलब है कि 2018 में जारी अपने दिशानिर्देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन के समय ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के लिए पृथक मापदंड जारी किये थे. इसके मुताबिक सड़क यातायात में दिन के समय शोर का स्तर 53 डेसिबल, रेल परिवहन में 54, हवाई जहाज और पवन चक्की चलने के दौरान 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए. इससे ऊपर का शोर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वायु प्रदूषण के बाद शोर स्वास्थ्य समस्याओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्यावरणीय कारक है. जाहिर है, शोर का बढ़ता स्तर खतरे का सूचक है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. बेशक कर्णप्रिय, हल्की और मधुर ध्वनि रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है, लेकिन परिवेश की ध्वनि जब शोर बन जाती है, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है. वायु और जल प्रदूषण की तरह ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है. यह एक अदृश्य खतरा है, जिससे बचकर न रहा जाये, तो यह हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली को प्रभावित कर सकता है. ध्वनि प्रदूषण को सभी आयु वर्ग और सामाजिक समूहों में एक शीर्ष पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ के रूप में देखा जाने लगा है. लंबे समय तक उच्च स्तर के शोर के संपर्क में रहने से मानव का स्वास्थ्य और विकास दोनों प्रभावित होता है. शोर लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है. अवांछित और अप्रिय शोर हमें परेशान कर सकता है और तनावग्रस्त बना सकता है. इससे नींद में खलल पड़ती है. नींद खराब होने से सेहत प्रभावित होती है. उच्च ध्वनि का श्रवण हमारे सुनने की क्षमता को कमजोर कर बहरेपन की ओर ले जाता है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनियाभर में लगभग डेढ़ अरब लोग इस समय कम सुनाई देने की अवस्था के साथ जीवन गुजार रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि 2050 तक दुनिया में हर चार में से एक व्यक्ति यानी लगभग 25 प्रतिशत आबादी किसी न किसी हद तक श्रवण क्षमता में कमी की अवस्था के साथ जी रही होगी. ऐसे में कानों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है. माना जाता है कि 85 डेसिबल या इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी व्यक्ति के कानों को नुकसान पहुंचा सकती है. चिकित्सकों के अनुसार, तेज आवाज के संपर्क में आने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव होता है. उच्च ध्वनि क्षेत्रों में रहने से याददाश्त में कमी, ध्यान लगाने में परेशानी, पढ़ाई–लिखाई प्रभावित होना भी आम बात है. जो लोग ऐसे इलाकों में लंबे समय तक रहते हैं, वे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत जोर से बोलना शुरू कर देते हैं और उन्हें धीमी आवाज सुनने में भी परेशानी होने लगती है. अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी वे अक्सर चिल्ला देते हैं, जिससे उनके शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ध्वनि प्रदूषण के चलते होने वाली श्टिनिटसश एक आम बीमारी है, जिसे कान बजना भी कहा जाता है. मानव कान अनुश्रव्य (20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति) और पराश्रव्य (20 हजार हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति) ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है, लेकिन लगातार शोर के संपर्क में रहने से मानव कान कमजोर होते जा रहे हैं. इससे कानों में झनझनाहट की शिकायत बढ़ती जा रही है. कानों में लगातार उच्च आवृत्ति बच्चों के कान के पर्दे को कमजोर कर सकता है, जिससे कुछ आवृत्तियों को सुनने में असमर्थता भी शामिल है. द इंडियन जनरल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण भ्रूण, शैशवावस्था और किशोरावस्था सहित विकास के किसी भी चरण में बच्चे की सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. स्कूल या घर में अवांछित या तेज आवाज बच्चों के लिए सीखने की क्रिया को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है. इससे संचार एवं भाषण कौशल के विकास और सर्वांगीण प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है.ऐसे में बच्चों को शांत माहौल उपलब्ध कराना अभिभावकों का प्रमुख कर्तव्य बन जाता है. बहरहाल, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के तहत शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल, आवाज वाले पटाखा फोड़ने, हॉर्न बजाने और ऊंची आवाज में संगीत गाना और वाद्ययंत्र बजाना प्रतिबंधित है. अगर हम अपने–अपने स्तर पर शोर करना बंद कर दें, तो पूरा परिवेश शांत हो सकता है.

श्रीलंका में समाधान की संभावना कम

डॉ धनंजय त्रिपाठी

पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका में घटनाक्रम तेजी से बदला है, पर इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है. बेहद गंभीर आर्थिक संकट के कारण वहां समाज और राजनीति में कई महीने से अस्थिरता व्याप्त है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ऐसा लगता है कि यह अनिश्चित माहौल अभी बना रहेगा. मई में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में नयी सरकार गठित हुई थी.इस बदलाव के बावजूद हालात बद से बदतर होते गये. महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री रहते ही श्रीलंका एक प्रकार से दिवालिया हो गया था और उसके पास विदेशी कर्ज चुकाने या बाहर से चीजें आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी. उनके पद से हटने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रहे थी कि उनके भाई गोटाबया राजपक्षे भी जल्दी ही राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे और नये सिरे से नये कार्यक्रम के तहत सरकार संकट से निकलने का प्रयास करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और गोटाबया राजपक्षे राष्ट्रपति बने रहे.चूंकि जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, तो आक्रोश भी गहन होता जा रहा था. खबरों में हम पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें देख रहे हैं, वह समस्या तो है ही, पर उसके साथ–साथ जीवनरक्षक दवाओं की भी बड़ी कमी हो गयी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण उनका आयात करना संभव नहीं हो रहा है. मुद्रास्फीति इतनी अधिक है कि आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न लोग ही खाने–पीने की चीजों और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीद कर पा रहे हैं. इन चीजों की उपलब्धता भी बहुत घट चुकी है. मध्य आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और गरीबों की स्थिति बेहद खराब है. इन मुश्किलों से किसी प्रकार की राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे थे. ऐसे में जनाक्रोश अनियंत्रित हो गया और लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों पर कब्जा कर लिया. प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा की पेशकश की है और राष्ट्रपति गोटाबया ने पद छोड़ने की बात कही है. जनता का गुस्सा भड़कने की एक अहम वजह यह भी है कि सर्वोच्च पदों पर आसीन इन दोनों नेताओं के द्वारा हालात सुधारने के लिए कोई ऐसी पहलकदमी भी नहीं हो रही थी कि लोग कोई उम्मीद देखते. यह संकेत भी लोगों में जा रहा था कि राजपक्षे की प्राथमिकता श्रीलंका की सत्ता और राजनीति में अपने वर्चस्व को बचाने की है, न कि देश को इस भारी मुसीबत से निकालने की. श्रीलंका के लोग इस आर्थिक संकट के लिए पूरी तरह से राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानते हैं. इसकी दो वजहें हैं. साल 2009 से ही यह परिवार किसी न किसी तरीके से सरकार या राजनीति में हावी रहा है. महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली हालिया सरकार की बात करें, तो श्रीलंका के राष्ट्रीय बजट का 70 प्रतिशत हिस्से का नियंत्रण राजपक्षे परिवार के मंत्रियों के हाथ में था. वह सरकार एक के बाद लायी जा रही गलत नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे थी. पिछले एक–दो साल में जब स्थिति बिगड़ने के स्पष्ट संकेत आने लगे थे, तब भी सरकार ने किसी भी तरह का उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया. जैविक खेती की नीति से पैदावार में बड़ी कमी आयी, जिससे किसानों की आमदनी तो घटी ही, बाजार में चीजें काफी महंगी हो गयीं. कोविड महामारी ने पर्यटन कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. राजपक्षे परिवार के हाथ पर हाथ धरे रहने से जनता में बनी उसके भ्रष्ट होने और सत्ता को पकड़े रहने की छवि को और मजबूती मिली. एक नाराजगी यह भी रही है कि गोटाबया ने यह तो कह दिया है कि वे इस्तीफा दे देंगे और शायद दे भी दें, पर श्रीलंका की संवैधानिक व्यवस्था में त्यागपत्र की वैधता तभी होती है, जब वह लिखित रूप में हो. अभी तो यह भी पता नहीं है कि वे राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद कहां गये हैं. यह स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि श्रीलंका की स्थिति ठीक होने में लंबा समय लगेगा. आर्थिक स्थिति इतनी चौपट हो चुकी है कि किसी चमत्कार से ही उसका कोई तुरंत समाधान हो सकता है. अभी कुछ समय के लिए यही हो सकता है कि श्रीलंका के पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तात्कालिक तौर पर मदद मुहैया कराएं, ताकि लोगों को राहत मिले तथा देश को आगे का रास्ता निकालने की मोहलत मिले. अब तक भारत ने बड़े पैमाने पर सहायता की है और आगे भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. भारत की ओर से इस संबंध में सकारात्मक संकेत भी दिये गये हैं. यह इसलिए भी जरूरी है कि अगर इस द्वीपीय देश में अस्थिरता बढ़ती है, तो भारत भी उसके असर से अछूता नहीं रहेगा. वहां भारत की जो अच्छी छवि है, उसे बरकरार रखना भी आवश्यक है. भारत की वर्तमान विदेश नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना अहम आयाम है. इसके लिए भी श्रीलंका का मसला एक बड़ी चुनौती है. हालांकि भारत जैसे देशों की सहायता का बड़ा महत्व है, लेकिन बड़े पैमाने पर राहत और भविष्य के लिए मजबूत आधार जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से बेलआउट पैकेज मिले, जिसके लिए चर्चा भी हो रही है. इसके अलावा भारत, जापान समेत कुछ देशों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव भी है. पर यह सब तब ही हो सकेगा, जब श्रीलंका में कुछ राजनीतिक स्थिरता आए और जो नयी अंतरिम सरकार बनेगी, उसका रवैया भी बड़ा निर्धारक हो. संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संसद के सभापति अंतरिम रूप से सरकार गठित कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता राजपक्षे परिवार और उनकी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति को स्वीकार करेगी. कौन–कौन पार्टियां संयुक्त सरकार में शामिल होंगी और कौन–कौन बाहर रहती हैं, यह भी देखा जाना है. राजनीतिक दलों के लिए भी यह संकट का समय है. रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद लेकर और असफल रह कर अपना बड़ा नुकसान कर चुके हैं. चूंकि बहुत जल्दी देश इस मुश्किल से बाहर आ पाने की स्थिति में नहीं है, तो पार्टियां भी सोच–समझ कर जिम्मेदारी लेना चाहेंगी, ताकि कोई दोष उनके सिर न आए. महिंदा राजपक्षे भी सभी पार्टियों को लेकर सरकार बनाना चाहते थे, पर सहमति नहीं बन सकी. ऐसा विक्रमसिंघे के साथ भी हुआ. एक पहलू यह भी है कि ऐसे समय में चुनाव पर खर्च कराना समझदारी की बात होगी और अगर चुनाव होता है, उसका खर्च कहां से आयेगा.

बढ़ता तापमान बढ़ा रहा चक्रवातों का खतरा

सुदर्शन सोलंकी

चक्रवाती तूफानों को कम करने एवं उनसे होने वाले विनाश से बचने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा और बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए सभी राष्ट्रों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचना, प्रदूषण पर नियंत्रण एवं वनों की कटाई को रोकना जैसी कई योजनाओं पर कार्य करना होगा। हमारे द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे अनैतिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप पृथ्वी की जलवायु पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और यही कारण है विश्व में चक्रवातों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। चक्रवात समुद्र से ऊर्जा ग्रहण करता है और फिर पृथ्वी की ओर आक्रामक रूप से बढ़ता है। इसमें अत्यधिक प्रचंड वेग और ऊर्जा होती है। इसकी संरचना अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी होती है। जब यह 150 से 300 कि.मी. के वेग से पृथ्वी की सतह से टकराता है तो भीषण आंधी और तूफान के साथ धरती को अत्यधिक प्रभावित करता है। तापमान अधिक होने से समुद्र की सतह भाप में परिवर्तित होकर भंवर के रूप में सीधे आकाश की ओर जाती हैय इस बवंडर से समुद्र की सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। हवा गरम होकर जैसे ही ऊपर उठती है आसपास की ठंडी हवा खाली जगह भरने को आ जाती है, यह हवा भी गरम हो जाती है और अपने साथ पानी लेकर ऊपर उठती है। इस तरह लगातार ऊपर उठती हवाएं पानी के बादलों का कुंडली की तरह एक वृत्त बना लेती हैं जो एक चक्र की तरह घूमने लगता है। चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इस बिंदु को चक्रवात की आंख कहते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया तूफान आसानी गंभीर चक्रवात में बदल गया था। भारत में चक्रवाती तूफान अधिकांशतरू मई और अक्टूबर के बीच आते हैं। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं और पूर्वी तटरेखा पर उनका असर दिखता है। वर्ष 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के अलावा आइला, पाइलिन, हुदहुद, गज, तितली और फानी जैसे तूफान पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में आए हैं। साल 2021 में अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान शताऊ तेश अनुकूल मौसमी कारकों की वजह से विनाशकारी हुआ था लेकिन अब अरब सागर में भी लगातार चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चक्रवाती तूफान का नामकरण–ट्रॉपिकल चक्रवात एक बार में एक हफ्ते या उससे अधिक समय तक बने रह सकते हैं। ऐसे में एक समय में एक से अधिक चक्रवाती तूफान होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए तूफान को एक नाम दिया जाता है जिससे पूर्वानुमान करते समय वैज्ञानिकों में भ्रम की स्थिति नहीं रहे। भारत के मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हाल ही में भविष्य के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों की एक सूची जारी की है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होंगे। दुनिया भर के हर महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा रखा जाता है। वैसे तूफानों का औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। इससे पहले तूफानों के नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे। इसलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर होते थे। 70 के दशक से यह परंपरा बदल गई और तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर रखे जाने लगे। सम संख्या वाले वर्षों में तूफानों के नाम महिलाओं के नाम और विषम संख्या वाले वर्षों में पुरुषों के नाम पर होते थे। वर्ष 2004 से विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। आठ उत्तरी हिंद महासागरीय देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका व थाईलैंड) एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 (हर देश आठ) नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन आठों देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन आठ देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। फ्लोरिडा के तट से उठने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं जबकि फिलीपींस के तट पर यह टायफून हो जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठते हैं और टायफून प्रशांत से। हरिकेन और टाइफून जलीय तूफान है जो पानी की सतह से उठते हैं, वहीं जमीन पर उठने वाले तूफान को टॉरनेडो कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान समुद्र सतह का तापमान भी बढ़ा रहा है जिससे चक्रवात अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो रहे हैं। अरब सागर में समुद्र सतह का तापमान 28–29 डिग्री सेल्सियस तक रहता है किंतु ताऊ ते तूफान के समय यह 31 डिग्री था। एक अनुमान के आधार पर सबसे शक्तिशाली तूफानों की ताकत हर दशक में करीब 8 प्रतिशत तक बढ़ रही है। पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 2001 से 2019 के बीच अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अत्यंत गंभीर चक्रवातों में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्ययन के अनुसार, 1982 से 2000 के बीच 92 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए थे जिनमें से 30 प्रतिशत अत्यंत गंभीर तूफान श्रेणी में बदल गए थे। जबकि 2001 और 2019 के बीच संख्या बढ़कर 100 हो गई थी, जिनमें से 36 प्रतिशत अत्यंत गंभीर रहे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर दी इंडियन रीजन नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए गए तो ग्रीष्म लहरों में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है और समुद्र का जलस्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मौसमी कारकों की वजह से उत्तरी हिन्द महासागर में अब और अधिक शक्तिशाली चक्रवात तटों से टकराएंगे। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसटन युनिवर्सिटी और यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर बदलती जलवायु की समीक्षा करके निष्कर्ष निकाला है कि यदि वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो चक्रवाती हवा की अधिकतम गति में 5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है जिससे चक्रवाती हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाएगी जो पृथ्वी पर बड़ी आपदा के लिए पर्याप्त है।

भुखमरी का प्रहार

खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में भुखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है। पूरी दुनिया में 2.3 अरब लोगों को भोजन सामग्री जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह आंकड़ा 2021 का है, जिसमें कोरोना संकट के घातक प्रभाव भी निहित हैं। इस साल शुरू हुए रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद अनाज, पेट्रोलियम पदार्थों व खाद आदि के दाम बढ़ने से आज पूरी दुनिया जिस चुनौती का सामना कर रही है, उसके बाद की भयावह स्थिति का अंदाजा स्वतरू ही लगाया जा सकता है। विडंबना ही है कि पूरी दुनिया में भुखमरी, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण को दूर करने के लिये पिछले दशक में जो प्रयास किये गये थे, उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि वर्ष 2030 तक भूख,खाद्य असुरक्षा व कुपोषण को खत्म करने के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें पूरा करना अब मुश्किल नजर आता है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में खाद्य संकट से प्रभावित देशों में बारह देश अफ्रीका से, एक कैरिबियन देश हैती व दो एशिया से अफगानिस्तान व यमन हैं। इस भुखमरी के मूल में जहां सशस्त्र संघर्ष, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी व गरीबी का दायरा है, वहीं कुशासन की भी बड़ी भूमिका है। निस्संदेह, पहले कोरोना महामारी और फिर यूक्रेन संकट ने इस विभीषिका को विस्तार ही दिया है। यही वजह है कि दुनिया के करीब तीन अरब लोग स्वस्थ व्यक्ति के लिये जरूरी खुराक जुटाने में असमर्थ हो गये हैं। यह संकट तथाकथित आधुनिक विकास के उस मॉडल पर सवालिया निशान लगाता है जो दुनिया में विज्ञान व तकनीक की क्रांति का दंभ भरता हुआ एकांगी विकास को बढ़ावा दे रहा है। एक तरफ समृद्धि व संपन्नता लहरा रही है तो दूसरी तरफ अरबों लोगों के जीवन में विपन्नता का अंधेरा गहरा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि विभिन्न देशों की सरकारें आर्थिक विसंगतियां दूर करने को ईमानदार प्रयास क्यों नहीं करती। इस संकट को दूर करने के लिये कारगर रणनीति क्यों नहीं बनती , जिसके चलते भुखमरी व कुपोषण का संकट विकराल रूप में उपस्थित होता है। विश्व में करीब तीन अरब लोगों का स्वस्थ जीवन के लिये जरूरी खुराक न जुटा पाना इसकी बानगी है। हालांकि, पहले से जारी संकट को बढ़ाने में कोरोना संकट के दौरान उपजी महंगाई की बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके मूल में सत्ताधीशों की काहिली भी है। कहना कठिन है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिये लागू किये गये कठोर उपायों से कितना संक्रमण रुका,लेकिन गरीबी की दलदल को इसने जरूर बढ़ा दिया। सवाल उठता है कि विभिन्न वैश्विक संस्थाएं व इन मामलों के विशेषज्ञ गरीबी–भुखमरी दूर करने के लिये दूरगामी रणनीति क्यों नहीं तैयार करते। यही वजह है कि इस संकट से निबटने के लिये बनायी रणनीतियां व्यावहारिक धरातल पर कारगर साबित नहीं हो रही हैं। व्यवस्था के छेद व भ्रष्टाचार इस संकट को सींच रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि कुदरत ने हर व्यक्ति का पेट भरने का इंतजाम किया है लेकिन संसाधनों के अन्यायपूर्ण बंटवारे ने गरीबी–भुखमरी को जन्म दिया है। पहले उपनिवेशवाद,फिर साम्राज्यवाद और अंततरू विकसित देशों के हितों के मद्देनजर बनी वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अमीरी–गरीबी की खाई को लगातार चौड़ा किया है। कोरोना संकट में भारत तथा विदेशों में गरीबी का विस्तार और अरबपतियों की संख्या में इजाफा इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का सच है। जरूरी है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करके खाद्य असुरक्षा व भुखमरी के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाये। कैसी विडंबना है।

प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ–साथ लोगों की रक्षा भी होती है क्योंकि इस पद्धति में जानलेवा रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है. प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि यह आर्थिक सफलता का माध्यम भी है. इस विषय पर गुजरात के सूरत में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने श्सूरत मॉडलश से सीख लेने को कहा. वहां हर पंचायत से 75 किसानों को इस पद्धति से खेती करने के लिए चुना गया है. वर्तमान में 550 से अधिक पंचायतों के 40 हजार से ज्यादा किसान प्राकृतिक कृषि को अपना चुके हैं. इस पद्धति के तहत किसी तरह के रसायन का उपयोग नहीं होता है और परंपरागत तरीके से खेती की जाती है. दो वर्ष पहले नीति आयोग की अगुवाई में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम की शुरुआत की गयी थी. इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है. गुजरात के अलावा इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में भी कई क्षेत्रों में अपनाया गया है. अन्य कुछ राज्य भी इस प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं. यह स्थापित तथ्य है कि पैदावार बढ़ाने के लिए रसायनों के बेतहाशा इस्तेमाल से खाद्य प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कैंसर जैसी भयावह बीमारियां महामारी बनती जा रही हैं. व्यावसायिक फसलों का चलन बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ रही है. भूजल के अनियंत्रित दोहन ने जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है. अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों, खादों और संकर बीजों तथा पानी के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है. जलवायु परिवर्तन और धरती का बढ़ता तापमान भी पैदावार पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं. आज भले ही भारत खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो, लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जायेगा।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 18 जुलाई, 2022

युसुफ अली के लुलु मॉल की फायर सेफ्टी की सूचना एक्टिविस्ट को देने से इंकार

लखनऊ(यूएनएस)। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुलतानपुर रोड के पास शहीद पथ के बगल में सुशांत गोल्फ सिटी में करीब 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से लगभग 11 एकड़ इलाके में बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा लुलु नाम का मॉल बीती ईद पर हुए उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए खुल गया है. लुलु मॉल के मालिक केरल निवासी एम. ए. यूसुफ अली हैं जो लुलु ग्रुप इंटरनैशनल नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन हैं जिसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में है. बताते चलें कि लुलु अरबी का शब्द है जिसका मतलब मोती होता है. लुलु ग्रुप का सालाना टर्नओवर लगभग 8 अरब डॉलर का है.लुलु ग्रुप का बिजनेस मध्य पूर्व, एशिया, अमेरिका और यूरोप में समेत 22 देशों में है जिसमें करीब 57 हजार लोगों को रोजगार मिला है. भारत में कोच्चि, बेंगलुरू और तिरुवनंतपुरम के बाद लुलु ग्रुप का यह चौथा मॉल है। लुलु मॉल लखनऊ आम जनता के लिए खुल तो गया है लेकिन लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासिनी आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की आरटीआई पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब से इस मॉल की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल एक्टिविस्ट उर्वशी ने बीते जून महीने की 12 तारीख को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जन सूचना अधिकारी को आरटीआई अर्जी देकर लखनऊ स्थित लुलु इंडिया शौपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड के मॉल की फायर सेफ्टी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जन सूचना अधिकारी और अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ श्रवण कुमार सिंह ने बीती 6 जुलाई को उर्वशी को पत्र जारी किया है और अपने इस पत्र के साथ लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह की बीती 29 जून की आख्या नत्थी करके उर्वशी को भेजी है। एक्टिविस्ट उर्वशी बताती हैं कि विजय कुमार सिंह की आख्या से स्पष्ट है कि विजय ने सूचना का अधिकार नियमावली के नियम 4(8) के तहत लुलु मॉल लखनऊ के प्रबंधक,भवन स्वामी को आरटीआई कानून की धारा 11 का नोटिस गिया था जिसका लिखित उत्तर लुलु मॉल लखनऊ के प्रबंध भवन स्वामी ने बीती 23 जून को बाकायदा पत्र लिखते हुए विजय को दिया है। विजय कुमार सिंह ने अपनी आख्या में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लुलु मॉल लखनऊ के प्रबंधक, भवन स्वामी ने बीती बीती 23 जून के पत्र द्वारा लुलु मॉल की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सूचनाओं को गोपनीय मानते हुए इन सूचनाओं को एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा को आरटीआई में देकर सार्वजनिक करने में असहमति व्यक्त की है। उर्वशी कहती हैं कि लुलु मॉल के मालिक युसुफ अली और जनरल मैनेजर समीर वर्मा द्वारा लोगों को लुलु मॉल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर दावा किया जा रहा है कि मॉल में एक साथ 50 हजार लोग शॉपिंग कर सकते हैं, 16 हजार लोग बैठकर फूड कोर्ट में एक साथ खाना खा सकते हैं, पार्किंग में तीन हजार गाड़ियां पार्क हो सकती हैं और 11 स्क्रीन वाला पीवीआर सुपरप्लेक्स है, मॉल में गर्भवतियों और दिव्यांगों के लिए अति विशिष्ट सुविधायें हैं लेकिन एक बंद जगह में एक साथ इतनी बड़ी तादात में इकट्ठी होने वाली आम जनता को उनके जीवन की सुरक्षा से जुड़े इतने अहम सवाल कि आखिर इस मॉल की फायर सेफ्टी की व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं, को आम जनता से ही छुपाया जा रहा है जो इस मॉल के स्वामी और प्रबंधक के वैचारिक और व्यवहारिक दोगलेपन को सामने ला रहा है. बकौल उर्वशी, मॉल एक सार्वजनिक स्थान है और आम जनता को यह जानने का पूरा हक है कि जिस मॉल में वह जा रहा रहे हैं आखिर वह ढांचागत और फायर सेफ्टी के लिहाज से उनके लिए सुरक्षित है या नहीं है।जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है, की बात कहते हुए उर्वशी ने युसुफ अली और समीर वर्मा को अल्ट्रा हाई एथिक्स के साथ व्यापार करने की सलाह सार्वजनिक रूप से दी है. साथ ही उर्वशी ने सूबे के सीएम से सार्वजनिक रूप से अपेक्षा की है कि वे वृहद लोकहित में आम जन के जीवन की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में दखल देकर लुलु मॉल लखनऊ की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की मानकों के अनुसार जांच कराकर इसकी पूरी जानकारी सम्बंधित सरकारी विभागों की वेबसाइटों के साथ–साथ लुलु मॉल लखनऊ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करायेंगे।

जेल अफसर केस, अंतिम आदेश 21 जुलाई को

लखनऊ(यूएनएस)। लखनऊ जेल के अफसरों द्वारा जानबूझ कर तमाम सामान व अभिलेख गायब करने के आरोप के संबंध में अमिताभ ठाकुर द्वारा एफआईआर दर्ज करने हेतु धारा 156 (3) सीआरपीसी में दिए गए प्रार्थनापत्र कर अंतिम बहस हो गयी है और सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला 21 जुलाई 2022 को सुनाया जायेगा। अमिताभ ठाकुर ने अपने वाद में कहा था कि उनके लखनऊ जेल में रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न प्राधिकारियों के लिए कुल 545 पत्र जेल प्रशासन को सौंपे जिनमे कुछ को छोड़ कर ज्यादातर पत्र गायब हैं. इसके साथ ही उनके कई अन्य अभिलेख व सामान भी जेल प्रशासन द्वारा उनके बार–बार अनुरोध के बाद उन्हें नहीं सौंपे गए हैं तथा गायब कर दिए गए हैं। अमिताभ ने कहा कि उनके बार–बार अनुरोध के बाद भी जानबूझ कर उन्हें प्रताड़ित करने तथा क्षति पहुंचाने के लिए उनके सामान व अभिलेख गायन किये गए हैं. अतः उन्होंने इसके संबंध में समुचित धाराओं में एफआईआर की मांग की है।

योगी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, मंदिर में की पूजा- अर्चना

लखनऊ(यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभ्यताओं का उदय, संस्कृतियों का उत्कर्ष व महान विभूतियों का निर्माण पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में ही होता है। अपने तप, त्याग और ज्ञान के आलोक से मानव समाज का उद्धार कर रहे सभी देवतुल्य गुरुजनों को नमन किया। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिर परिसर स्थित अपने पूज्य गुरु राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज व समस्त गुरुजन के समाधि स्थल पर पूजा–अर्चना की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर परदेसियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट कर कहा कि गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्य, संयम, शांति और सद्भावना की सीख देने वाले सभी गुरुओं को नमन। समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

वर्कर्स फ्रंट ने पीएम को पत्र ट्वीट कर इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वापस लेने की मांग की

लखनऊ(यूएनएस)। प्रस्तावित इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल–2022 के विरोध में बिजली कामगारों व अभियंताओं के देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी बीच वर्कर्स फ्रंट ने पीएम मोदी को पत्र ट्वीट कर आगामी संसद सत्र में पेश न करने और बिल को वापस लेने की अपील की है। वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश उपाध्यक्ष इं. दुर्गा प्रसाद द्वारा पीएम को प्रेषित पत्र में मत व्यक्त किया गया है कि इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल–2022 के प्रावधान राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं, खासतौर पर इससे किसानों व सौभाग्य योजना अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 5–7 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है, इसके अलावा डिस्कॉम के निजीकरण से पावर कारपोरेशन आदि सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के भविष्य खतरे में पड़ सकता है दरअसल इनकी नौकरी की गारंटी का प्रावधान बिल में नहीं है। मुंबई में बिजली वितरण के अडानी व अंबानी के प्रयोग के सफल होने का कोई ठोस अनुभव सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा कारपोरेट कंपनियों की ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति के टेंडर लेने में कतई दिलचस्पी नहीं होगी। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मुनाफा होगा उनमें कारपोरेट कंपनियों द्वारा नाममात्र के भुगतान पर डिस्कॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जायेगा। लेकिन जीर्णोद्धार आदि में भारीभरकम खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। इस तरह के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। वर्कर्स फ्रंट उपाध्यक्ष इं. दुर्गा प्रसाद ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों का अनुभव हमारे सामने है जिसके आधार पर ही आज उत्पादन क्षेत्र की कारपोरेट बिजली कंपनियों को मुनाफाखोरी व लूट की खुली छूट मिली हुई है।

स्वतंत्रता दिवस महज एक सरकारी कार्यक्रम बन कर ना रहे, हमें इसे जन–जन का उत्सव बनाना है : मुख्य सचिव

लखनऊ(यूएनएस)। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिसमें मुख्य सचिव के समक्ष विभिन्न विभागों ने उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर पीपीटी प्रस्तुत की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस बाकी के कार्यक्रमों से काफी अलग और खास है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं हमें इसे विशेष तरीके से मनाना है। हम बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं। हर एक जिला इसे एक इवेंट के तौर पर तैयार करे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी जगहों पर कार्यक्रम हों। मुख्यमंत्री का आदेश है इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, बाजार बंद नहीं होगा। आजादी के अमृत पर्व पर हर तरफ उत्सव का माहौल रहे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस महज एक सरकारी कार्यक्रम बन कर ना रहे, हमें इसे जन–जन का उत्सव बनाना है। इसके लिए समाज के हर एक वर्ग को हर तबके को हर सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी कैडेट, नेहरू युवा केंद्र, गांव के नवयुवक मंगल दल, महिला स्वयंसेवी संगठनों, खेल ज्यूडिशरी, व्यापारी संगठन आदि को जोड़ें। हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता सप्ताह से जुड़े ऐसी हमारी कोशिश हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बलिदानी वीरों, सेना और पुलिस के शहीदों के परिजनों को ब्लॉक पर जिले में कार्यक्रमों में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाए। इस दौरान हम उन्हें उपहार में जिले के प्रसिद्ध ओडीओपी से जुड़े उत्पाद दे सकते हैं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि दिवाली पर्व की तरह स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत पर्व पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है इसके लिए सभी अंतर्विभागीय समन्वय को पूरा करके तेजी से अब तक की कार्यवाही और रिजल्ट का रिव्यू कर लिया जाए ताकि जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पहले से तैयारी रहे। हमें इसे नेशनल पब्लिक मूवमेंट बनाना है। स्वतंत्र सप्ताह उत्सव में हर दिन कोई ना कोई विशेष आयोजन हो। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर अगर कहीं बारिश हो तो ऐसे समय में कहीं भी जलभराव ना होने पाए इसके लिए पहले से ही नालियों, ड्रेनेज की साफ सफाई करा ली जाए। हर घर झण्डा अभियान के तहत सभी जनपदों में झंडा वितरण की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करके समय–समय पर रिव्यू होता रहे। 30 जुलाई तक हर हाल में झंडे निर्धारित जगहों तक पहुंच जाएं। झंडा फहराते समय पूरी सावधानी के साथ में झंडा एक्ट के पालन को सुनिश्चित किया जाए। कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। निर्धारित कलर, चिन्ह, आकार के झंडे फहराए जाएं। साथ ही सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों ने खादी के झंडों का प्रयोग हो। डीएम चंदौली की डेथ नोटिफिकेशन सर्विस की प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि डेथ नोटिफिकेशन सर्विस बहुत ही प्रभावी कदम है। इसे आधार से भी जोड़ा जाए। ताकि सभी संबंधित विभागों तक एक साथ सूचनाऐं स्वचलित रूप से प्राप्त हो जाए। जिससे मृतकों के परिवार वालों को समय से त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है। मृत्यु उपरांत समस्त देयकों का लाभ मृतक के परिवार तक समय से सीधे पहुंचेगा। हम उस उनके दुख में शामिल हो सकेंगे सरकार उनके साथ साथ खड़ी दिखेगी। जिससे राजस्व की बचत के साथ सेवा और सुशासन यानि गुड गवर्नेंस का संकल्प पूरा होगा। डीएम रामपुर की सुपोषित रामपुर की प्रस्तुति पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आपका प्रोडक्ट कुपोषण कुपोषित बच्चों के लिए वरदान है। आपके पास सुखद परिणाम भी है और प्रमाण भी है। इसकी अच्छे से मार्केटिंग कर इसका ब्रांड बनाकर इसको बाकी जिलों के लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश हो। ताकि पूरे प्रदेश को इस प्रोडक्ट का लाभ मिले और कुपोषण को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्नाव के डीएम की बहुद्देशीय पंचायत परिसर मॉडल की प्रस्तुति पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से अन्य जिलों को भी सीख लेनी चाहिए। एक प्रकार से यह वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। जहां पर जन कल्याण से जुड़ी सारी सेवाएं मौजूद होंगी। सेवाओं से जुड़े सारे स्थानीय अधिकारी उपलब्ध होंगे। इस प्रकार जनता के हित में विभागों के तालमेल का बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। डीएम अमरोहा की जनसुनवाई सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयासों की तारीफ करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं जहां पर जनता और जनता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। हमें राजा और प्रजा के युग से बाहर निकलना है। हमें जनता के प्रति संवेदना का भाव रख ऐसा माहौल बनाना है जहां पर आमजन के भीतर किसी प्रकार का डर, संकोच ना हो। लोग बेधड़क, बेखौफ होकर अपनी समस्याएं बता सकें। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पीने का पानी शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध हो। जहां सम्मान के साथ उनकी समस्या की सुनवाई हो। सीडीओ कानपुर के स्मार्ट गांव प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बाकी के गांवों को भी इसका लाभ मिले इसके लिए हम सबको इस प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना पर काम करना चाहिए। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के आकांक्षात्मक जनपदों के विकास के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। ठीक इसी प्रकार से हमें सौ आकांक्षात्मक विकास खंडों के विकास पर कार्य करना है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ऐसे ब्लॉकों पर कर्मठ और उत्साही अधिकारियों की तैनाती शत् प्रतिशत् सुनिश्चित की जाए। अपने अपने लेवल पर लगातार मॉनिटरिंग और प्राथमिकता आधारित लोक कल्याण की योजनाओं की मॉनिटरिंग व सत्यापन कार्य जारी रहे। उन्होंने कहा कि इन ब्लॉकों के लिए नोडल ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारियों को बनाया गया है जो लगातार योजनाओं की प्रगति का आंकलन करते रहें।

एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन

लखनऊ(यूएनएस)। लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के नं 1 सैन्य प्रशिक्षण बटालियन में 4 से 13 जुलाई तक आयोजित 64 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 218 का 13 जुलाई को समापन हो गया। लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी जिलों के कैंप कैडेटों द्वारा 12 जुलाई को भव्य सांस्कृतिक एवं मनोरंजन का कार्यक्रम पेश किया गया। इस ,अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि नंबर 1 सैन्य प्रशिक्षण बटालियन के मेजर राकेश चंदर थे। कैडेटों का प्रदर्शन जोश, ऊर्जा और कौशल से भरपूर था और लगभग 500 कैडेटों और कर्मचारियों की भारी भीड़ ने इस की सराहना की। 64 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गौरव कार्की ने शिविर की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने और सांस्कृतिक एवं विविध कार्यक्रमों के लिए इतनी अच्छी तैयारी करने के लिए सभी कैडेटों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने खेल–कूद, फायरिंग और पेंटिंग सहित सभी प्रतियोगिताओं में विजेता और उप विजेता को पदक देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर के समापन अवसर पर अपने संबोधन में गौरव कार्की ने सभी कैडेटों, प्रशिक्षण कर्मचारियों, यूनिट सिविल स्टाफ, राज्य सरकार के मेडिकल स्टाफ को इसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप मुखर्जी और उनके सैन्य अधिकारियों एवं अन्य रैंकों के सैन्य कर्मियों को पूरे दिल से सभी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्नल कार्की ने कहा कि उनके सहयोग के बिना इस शिविर की संभावना और बड़ी सफलता नहीं हो सकती थी।

लूलू मॉल में पहले दिन रिकॉर्ड एक लाख से ज्यादा लोगों की भीड़

लूलू हाइपरमार्केट और फंटुरा प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने

लखनऊ(यूएनएस)। लूलू माल लखनऊ अपने शुरुआत के पहले दिन ही एक लाख से अधिक विजिटर्स का गवाह बना, जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा 1.25 लाख के ऊपर पहुंच गया। यह रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहला दिन कहा जा सकता है। लूलू ग्रुप का फ्लैगशिप, लूलू हाइपरमार्केट, और सबसे बड़ा इनडोर फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर–फंटुरा, आगंतुकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया। बच्चे और बड़ों ने एक साथ कैरुसेल, मिनी कोस्टर्स, ड्राप टावर्स, नॉवेल्टी गेम्स, वीआर–सक्षम एडवेंचर एरीना गेम्स, आर्केड वीडियो गेम्स, एक्सडी थियेटर इत्यादि का लुफ्त उठाया। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की पेशकश करने वाले विशाल फूड कोर्ट को भी दर्शकों ने सराहा। इसी तरह, परिवार लूलू हाइपरमार्केट का आनंद ले रहे हैं, जिसमें लूलू फैशन स्टोर और लूलू कनेक्ट शामिल हैं, जो ग्रोसरी (फल और सब्जियां, फ्रेश फूड, बेकरी, डेयरी, पिज्जा और स्नैक्स, हॉट फूड, रोस्टरी और स्वादिष्ट भोजन), हेल्थ और ब्यूटी, घरेलू जरूरतों, गारमेंट्स, शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, घरेलू उपकरणों सहित वैश्विक और स्थानीय शॉपिंग के अनेक विकल्प पेश करते हैं। इसके अलावा, अधिकांश आगंतुकों ने मॉल की खुली जगहों का भी आनंद लिया। 'लूलू मॉल लखनऊ के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने कहा," लखनऊ के लोगों से हमें जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे हम अभिभूत हैं। पहले ही दिन एक लाख से अधिक लोगों का मॉल मे आना यह दर्शाता है की लूलू मॉल के लिए लखनऊवासियों में कितना उत्साह था। हमें जो प्यार मिला है, उसके लिए हम आभारी हैं और हमें यकीन है कि लूलू मॉल लखनऊ अब उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदारी और फुरसत के पल गुजारने के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा। अमर शहीद पथ, गोल्फ सिटी में स्थित 2.2 मिलियन वर्ग फुट में फैले लूलू मॉल लखनऊ ने भारत में कुछ सबसे बड़े ब्रांडों को जगह दी है जिसमें लूलू हाइपरमार्केट, लूलू फैशन स्टोर, लूलू कनेक्ट, यूनीक्लो, डेकाथलॉन, स्टारबक्स, नायका लक्स, कल्याण ज्वैलर्स, कोस्टा कॉफी और चिलीज जैसे अन्य ब्रांड शामिल हैं। यहाँ आने वाले लोगों के विविध स्वाद के लिए, मॉल में 15 बढ़िया भोजन रेस्तरां और कैफे हैं, और 25 ब्रांड आउटलेट के साथ एक विशाल फूड कोर्ट है जिसमें 1600 लोगों के बैठने की क्षमता है। लूलू मॉल लखनऊ में सबसे अच्छे आभूषण, फैशन और प्रीमियम वॉच ब्रांड्स के साथ एक डेडिकेटेड वेडिंग शॉपिंग एरिना भी है।

इटौंजा नगर पंचायत में विकास कार्य ठप

लखनऊ(यूएनएस)। इटौंजा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के कार्यालय न आने से क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इस नगर पंचायत क्षेत्र में दस वार्ड हैं। बख्शी का तालाब क्षेत्र में सबसे पुरानी इटौंजा नगर पंचायत है। अधिशासी अधिकारी के न आने से नगर पंचायत अध्यक्ष परेशान हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के अनुसार अधिशासी अधिकारी सिर्फ वेतन लेने आता है। उपजिलाधिकारी बख्शी का तालाब के औचक निरीक्षण में गायब मिले थे। बख्शी का तालाब क्षेत्र में इटौंजा नगर पंचायत का गठन 7 दिसम्बर 1988 में हुआ था। इस नगर पंचायत में दस वार्ड हैं। जिसमें लगभग दस हजार लोग निवास करते हैं। करीब सात पंचवर्षीय कार्यकाल खत्म होने के बावजूद इस नगर पंचायत में जलभराव और विकास कार्य की गति बहुत धीमी है। मौजूदा समय में इस नगर पंचायत की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसकी मुख्य वजह है कि यहां पर तैनात अधिशासी अधिकारी जगदीश वैश्य कार्यालय ही नहीं आते हैं।

गुरू पूर्णिमा पर अपने गुरूओं को किया नमन

लखनऊ(यूएनएस)। गुरू पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने जीवित या ब्रह्मलीन गुरूजनों को नमन करते है और उनको अपनी श्रद्धांजलि देकर याद करते है। इस अवसर पर राजधानी के प्रसिद्ध श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज व श्री योगानन्द बालिका इण्टर कालेज में गुरू पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से व उल्लासपूर्वक मनाया गया। अपने गुरूओं के प्रति कृतज्ञता व श्रद्धांजलि देते हुये गुरूकुल के संस्थापक योगानंद जी महाराज व संस्थापक प्रधानाचार्य डा0 महिपाल पाण्डेय के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। श्री योगेश्वर मठ में आयोजित गुरू पूर्णिमा समारोह में हवन–पूजन, गुरू पूजन के बाद प्रसाद वितरण के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर योगानन्द बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या साधना श्रीवास्तव, श्री योगेश्वर के प्रधानाचार्य डा0 जी0 के0 मिश्रा सहित सभी अध्यापक–अध्यापिकायें व छात्र–छात्रायें उपस्थित थी। पूर्व छात्रों ने भी किया अपने गुरूओं को नमन–इस अवसर पर विद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने उपस्थित होकर अपने गुरूओं को नमन किया। जिसम प्रमुख रूप सें पार्षद शिवपाल सांवरिया, पार्षद अजय दीक्षित, प्रसिद्ध हास्य कवि डा0 सर्वेश अस्थाना,, एम0डी0 शुक्ला कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य डा0 हरि नारायण उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

बाकेटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने लगाई जनसभा

लखनऊ(यूएनएस)। बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जनसुनवाई की। बुधवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं से सम्बंधित शिकायती पत्र प्राप्त किया। विधायक ने शिकायतों के निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिए सूचित किया है। क्षेत्र के अर्जुनपुर में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला द्वारा जनसुनवाई किया गया। बुधवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में चार दर्जन से अधिक शिकायती पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को विधायक से अवगत कराया। विधायक ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के शीघ्र निराकरण करने के कहा। अकडरिया खुर्द निवासी विजय कुमार यादव ने विधायक से शिकायत की है कि उनका खेत गोमती नदी से सटे गाटा संख्या 1021/1 और 1021/2 है। जिस पर लोग कब्जा कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की है।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 18 जुलाई, 2022

श्रद्धा के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा

जौनपुर। जिलें में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, उल्लास से मनाया गया। खास दिन पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं की ओर से गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्व को लेकर मठ–मंदिरों में भोर से भक्ति उल्लास है। आश्रमों में गुरु का आशीष प्राप्त करने के लिए दूर से लोग आये। नगर के सूर्यघाट स्थित राम जानकी मंदिर एवं बारी नाथ मठ सहित सहित अन्य इसी प्रकार के आस्था के केन्द्रों पर श्रद्धालुओं ने अपने वर्तमान व स्वर्गीय गुरूओ को नमन कर उनका आर्षीवाद लिया। पूर्णिमा पर श्रद्धालु आदि गंगा गोमती के विभिन्न घाटों पर स्नान कर पूजन किया। ज्ञात हो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरम्भ में आती है। इस दिन से चार महीने तक परिव्राजक साधु–सन्त एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये चार महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु–चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शान्ति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार, इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के चार मानसपुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा,यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदिगुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्तिकाल के संत घीसादास का भी जन्म इसी दिन हुआ था वे कबीरदास के शिष्य थे। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है– अंधकार या मूल अज्ञान और रु का का अर्थ किया गया है– उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन–शलाका से निवारण कर देता है।

राजस्व विभाग के अधिकतम विवादों का निस्तारण करायें

जौनपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के आदेशानुसार, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त दिन शनिवार को राजस्व के अधिकाधिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु तहसीलदारगण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स की बैठक सचिव विवेक विक्रम की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी, बैठक में तहसीलदार सदर, बदलापुर, केराकत, मछलीशहर, मड़ियाहूँ नायब तहसीलदार मड़ियाहूँ व समस्त पीएलवी गण उपस्थित रहे। सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित तहसीलदारगणों से निस्तारण योग्य मामलों को चिन्हित कर उसमें पक्षकारों पर नोटिस तामीला प्रभावी ढ़ग से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त तहसीलदारगण द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में राजस्व के अधिकतम वादों का सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु वादकारियों को नोटिस प्रेषित की जा रही है, उनके द्वारा लोक अदालत में अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त समस्त पीएलवी को निर्देशित किया गया कि आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

भू माफियाओं को सह देकर प्रधान करा रहे अवैध कब्जा

जौनपुर। सदर तहसील के उतरीजपुर गांव निवासी गोविन्द, ठाकुरदीन और राम आसरे पुत्र राम सूरत ने प्रदेष के मुख्यमंत्री को भेजे गये शिकायती पत्र में बताया कि गांव में सरकार की भूमि को भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करके भूमिधरी भूमि में चकमार्ग बनाया जा रहा था । उसे रोकने हेतु तथा अवैध रास्ता बनाने में सरकारी खर्च के भुगतान रोका जाय। आरोप लगाया कि प्रधान गांव के कुछ भूमाफियाओं को सह देकर ग्राम सभा सम्पत्तियों पर कब्जा करा रहे है। प्रार्थी के रकबे को भी प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कराया जा रहा है। वह धन बल व संख्या में कमजोर है इसका फायदा उठाकर उसकी जमीन पर विवाद की स्थिति में दफा 24 से भी सीमांकन कराने के उपरान्त कब्जा प्राप्त किया है। विक्रमाजीत पुत्र पांचू निवासी को भू माफिया में चिन्हित करते हुए ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा खाली कराया जाय।

एसडब्ल्यूएम के कार्य को गुणवत्ता पूर्ण करायें

जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा कार्यालय खंड विकास अधिकारी बक्सा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका, प्रधानमंत्री आवास रजिस्टर, ग्रांट रजिस्टर, अमृत सरोवर की फाइल सहित अन्य का विस्तृत निरीक्षण किया गया। ग्रांट रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान पाया कि रुपए 02 करोड़ 59 लाख अवशेष है जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि विस्तृत समीक्षा की जाए और संबंधित से स्पष्टीकरण लेने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आवास से संबंधित गांववार रजिस्टर बनाया जाए। एपीओ अंकित सिंह को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के रजिस्टर अपडेट रखें। परिसर में निष्प्रयोज्य बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि गांव में जाकर एसडब्ल्यूएम के कार्य को गुणवत्ता पूर्ण कराएं। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देशित किया कि जितने भी शौचालय अपूर्ण है उन्हें जल्द से जल्द बना दिया जाए। मीटिंग हॉल में वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम बनाए जाने हेतु निर्देशित किया। कार्यालय सीडीपीओ में जाकर खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि बीडीओ खुद खाद्यान्न का सत्यापन करें।

सीएमओ ने मरीजों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया

जौनपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 लक्ष्मी सिंह ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुफ्तीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बगथरी का निरीक्षण किया। चिकित्साधिकारी विनय कुमार राव वाह्य रोगी विभाग में मौजूद मिले। ओपीडी में मरीजों की संख्या कम दिखने पर सीएमओ ने मरीजों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया साथ ही साफ–सफाई सुनिश्चित कराने को कहा। फर्श खराब दिखने पर कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो माह पहले ही पत्राचार किया जा चुका है। अस्पताल में जहां भी मरम्मत की जरूरत दिखी उसे दुरुस्त कराने का संबंधित इंजीनियर को निर्देश दिया। एएनएम विनीता मूवमेंट रजिस्टर भरकर गांव में बने टीकाकरण स्थल बगथरी गईं थीं जबकि कैंसर पीड़ित फार्मासिस्ट जितेंद्रनाथ साह पत्र देकर अपना इलाज कराने बीएचयू गए थे।

इस पर सीएमओ ने डॉ राव से कहा कि अब सिर्फ पत्र से छुट्टी नहीं ली जाती। इसके लिए आनलाइन छुट्टी लेनी होती है। आगे से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से छुट्टी का आवेदन करवाइये। स्वीपर अशोक कुमार मौके पर मौजूद मिले। इसके बाद सीएमओ टीकाकरण स्थल पहुंचीं। वहां ड्यूलिस्ट के अनुसार टीका लगाया जा रहा था। टीकाकरण सत्र पर सभी टीके मौजूद दिखे। गर्भवती की सभी जांचें हो रहीं थीं। सीएमओ ने कोविड टीकाकरण से छूटे बच्चों का टीकाकरण यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। निडिल काटने वाला हब कटर काम नहीं कर रहा था जिसे बदलने का निर्देश दिया। सीएमओ के साथ एसीएमओ डॉ प्रभात कुमार मौजूद थे।

किसानों को खून के आसूं रुला रही विद्युत

जौनपुर। किसानों के बेहतरी व उनके आय को दुगना करने के लिए करोड़ों खर्च कर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक करोड़ों रुपए विद्युत विभाग पर खर्च किया जा रहा है।सरकार का प्रयास है कि किसानों के लिए सिंचाई के अनुकूल परिस्थिति बने रहें।

पर कुछ जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सरकार के इस प्रयास पर पानी फिरता दिख रहा है। क्योंकि धान की रोपाई का समय हो गया है। इस वक्त किसानों के खेतों के लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। पर प्रशासन शासन द्वारा किसानों को 5–7 घंटे भी बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। केराकत क्षेत्र के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है। दिशापुर(बजरंगनगर) फीडर,खडहर डगरा,नईबजार फीडर,अमिहित,सेनपुर की स्थिति तो और ही दयनीय है इस फीडरों पर हजारों छोटे बड़े किसान निर्भर है।अकेले बजरंगनगर दिशापुर मुख्य फीडर के दिशापुर फीडर से 64 गांव जुड़े है जिससे काफी किसान प्रभावित होतें है वही ब्रहामनपुर फीडर के 78 ग्राम जिनमे किसानों की काफी संख्या निर्भित है।इन फीडरों नें विद्युत के न आने के और विधुत कटौती के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।इन फीडरों से विधुत दिया तो जा रहा है पर पर किसान को पम्प से खेत मे पानी पहुचने के पहले विधुत कट जा रही है।इससे खेंतों में भरपूर पानी तो छोड़िए पानी ही पहुच नही पा रहा है।पानी न मिलने पर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। तब इसकी जिम्मेंदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा।

बस–ट्रक की टक्कर में ड्राइवर की मौत

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में रोडवेज बस और ट्रक की सीधी टक्कर में रोडवेज बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल ले जाने पर बेहतर उपचार हेतु वाराणसी बीएचयू रेफर कर दिया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। बताते है कि बुधवार को सवेरे पांच बजे गोरखपुर से प्रयागराज की तरफ रोडवेज की बस जा रही थी। गौराबादशाहपुर पुलिस चौकी के पास सामने से आ रहे ट्रक से दोनों वाहनों के चालकों की लापरवाही की वजह से आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना के बाद तेज आवाज को सुनकर जगे आसपास के दुकानदारों ने घायलों को बाहर निकालने के साथ तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने

दोनों वाहनों के चालकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां उपचार के दौरान लगभग सवा नौ बजे रोडवेज बस के चालक 36 वर्षीय धर्मेंद्र दुबे पुत्र अशरफीलाल निवासी दुगवल थाना सरायनाई, प्रयागराज की मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक 40 वर्षीय अनुपम 40 पुत्र लल्लू निवासी बनकट थाना पवारा जौनपुर को हालत गंभीर होने पर उपचार हेतु बनारस रेफर कर दिया गया। घटना में रोडवेज में सवार आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोरसंड पर उपचार करवाने के बाद छोड़ दिया गया और वह दूसरे वाहन से अपने गंतव्य को रवाना हो गए।

डिलीवरी के 48 घण्टे ना रूकने पर जताई नाराजगी

जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सा का औचक निरीक्षण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट गुलाब सिंह से दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली और पूछा कि किस बीमारी के मरीज अधिक आ रहे है और उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक सीएचसी एवं पीएचसी की प्रतिदिन की ओपीडी की रिपोर्ट दे। लेबर रूम निरीक्षण में सरिता देवी की डिलीवरी के उपरांत 48 घंटे नहीं रुकने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्टाफ नर्स को निर्देशित किया कि 48 घंटा रुकना सुनिश्चित किया जाए। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन दो से तीन डिलीवरी की जाती है। डॉ0 अनुराग द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि कुछ कर्मचारियों का अन्य जगह स्थानांतरण हो गया है, लेकिन उन्होंने आवास खाली नहीं किया है, इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहां की तत्काल उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सा के निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि मुख्य मार्ग से लेकर सीएचसी तक सफाई का विशेष अभियान चलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जितनी भी एंबुलेंस निष्प्रयोज्य हो चुकी है, उन्हें सीएचसी से हटाकर नीलाम करने की कार्यवाही की जाए। चिकित्सा अधीक्षक जी0के0 सिंह के द्वारा बताया गया कि कुल 100 मरीज देखे जा चुके हैं और इस समय सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज ज्यादातर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि टेलीमेडिसिन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे लोग घर बैठे ही परामर्श प्राप्त करें और उन्हें जिला अस्पताल या अन्य जगह न जाना पड़े। जिलाधिकारी ने लैब टेक्नीशियन के द्वारा की जा रही जांच के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि टीवी के सैंपल अधिक से अधिक लिए जाए। जिलाधिकारी के द्वारा आए हुए मरीजों से बात की और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। रन्नो दक्षिणपट्टी निवासी राधिका (12वर्ष) के जन्मजात पोलियो की बीमारी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसपर जिलाधिकारी ने डा0 आर सी यादव को निर्देशित किया कि बच्चें की हर–सम्भव इलाज कराकर अवगत कराये। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि मरीजों को बैठने के लिए कुर्सी, पेयजल, वेस्ट डिस्पोजल, वैक्सीन का रख–रखाव सहित विभिन्न दिशा–निर्देश दिए गए। डॉ0 आलोक रघुवंशी, डॉ0 मनीष सोनकर सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

व्यक्तित्व विकास के लिये ट्रेनिंग महत्वपूर्ण : वसुंधरा

जौनपुर। नगर की अग्रणी संस्था जेसीआई के अध्यक्ष डा. संदीप पाण्डेय के नेतृत्व में नगर के एक होटल में ओरिएण्टेशन ट्रेनिंग का आयोजन हुआ जिसकी मुख्य अतिथि रीजन डी की मण्डल उपाध्यक्ष वसुंधरा सिंह रहीं। इस मौके पर सर्वप्रथम अध्यक्ष डा. पाण्डेय ने सदस्यों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके पश्चात ट्रेनिंग प्रारम्भ की गयी । मुख्य अतिथि ने कहा कि जीवन में व्यक्तित्व विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में संस्था आपको सीखने का अवसर प्रदान करती है। पूर्व मण्डलाध्यक्ष राधे रमण जायसवाल ने कहा कि किसी

भी व्यक्ति को समाज का सच्चा नागरिक बनने के लिये सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है। मण्डल उपाध्यक्ष गौरव सेठ ने संस्था के सदस्यों से कहा कि आज की ट्रेनिंग जेसीआई के संदर्भ में सीखने का एक बड़ा अवसर अन्त में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के साथ मिलकर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। ट्रेनिंग में सत्य प्रकाश जयसवाल, विशाल तिवारी, दिलीप सिंह, आशुतोष जायसवाल, रमेश श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह, आशुतोष गुप्ता, अमर जौहरी, सौरभ जायसवाल, मनीष चौरसिया, कृष्ण गोपाल सहित अन्य लोग शामिल रहे। संचालन सचिव प्रदीप जायसवाल ने किया। संयोजक चित्रगुप्त वाचस्पति और आकाश केसरवानी ने आभार व्यक्त किया।

अब 24 घंटे तक खुलेगा रेलवे क्रासिंग का फाटक

जौनपुर। शाहगंज कस्बा वासियों के लिए राहत की बात है । कस्बे के पक्का पोखरा स्थित रेलवे क्रॉसिंग का फाटक अब पूरे 24 घंटे तक खुलेगा । अभी तक यह फाटक सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुलता था, जिससे लोगों को शाम के वक्त खुटहन रोड तक जाने के लिए जाम से जूझते हुए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। सीनियर सेक्शन इंजीनियर और स्टेशन अधीक्षक ने इसका शुभारंभ किया और इसे समाजसेवी देवी प्रसाद चौरसिया मंटू के लगातार कोशिशों का नतीजा बताया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैलाश नाथ और शाहगंज स्टेशन अधीक्षक वीके यादव ने सोमवार शाम फीता काटकर फाटक के 24 घंटे खुलने की सुविधा का शुभारंभ किया । सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि स्थानीय समाजसेवी देवी प्रसाद पिछले कई सालों से इस फाटक को पूरे समय तक खोले रखने की मांग अलग अलग मंच पर कर रहे थे । अब जाकर यह मांग मान ली गई। स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि बहुत पुरानी मांग पूरी होने से लोगों को राहत मिलेगी और इस क्षेत्र का भी विकास होगा।

मंदिर में गंदगी को लेकर किया हंगामा

जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव की सीमा पर स्थित निर्माणाधीन मंदिर में गंदगी व नाली का पानी बहाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मन्दिर के पास हंगामा किया। साथ ही पुलिस को पत्रक सौंप कार्रवाई की मांग की। गांव के महेंद्र यादव, राजनाथ यादव, रवि, जयनाथ यादव आदि ने बुधवार को प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को शिकायती पत्र देकर तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने एसएसआइ हरिनारायण पटेल को फोर्स के साथ मौके पर जांच–पड़ताल के लिए भेजा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामला दो पक्षों के बीच भूमि विवाद का है, जांच की जा रही है।

विवाहिता की मौत में पति सहित चार पर मुकदमा

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में मंगलवार को एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा गोपनीयता के साथ मायका और थाना पुलिस को बगैर सूचित किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की जानकारी होने पर देर रात थाने पर पहुँचें मृतका के पिता ने जेठ, जेठानी और पति के खिलाफ दहेज हत्या तथा साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले ग्राम प्रधान के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है। देर रात पुलिस ने पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम में संलिप्त दिखाए गए ग्राम प्रधान के प्रकरण की पुलिस छानबीन कर रही है। उक्त गॉव निवासी स्व0 रामदीन निषाद के पुत्र लालमन का विवाह चार वर्ष पूर्व सिकरारा थाना क्षेत्र के हरखपुर गॉव निवासी महेंद्र निषाद की पुत्री रंजना से हुआ था। महेंद्र का आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। आरोप है कि मंगलवार को ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मौत की सूचना भी ससुराल पक्ष के द्वारा हमें नहीं दी गई। शाम को दूर के रिश्तेदार से ज्ञात होने पर बेटी के घर पहुंचा तो पता चला कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सामूहिक दुष्कर्म का आधा दर्जन युवकों पर मुकदमा

जौनपुर। सरपतहा थाना क्षेत्र के अरसिया मोड़ पर एक दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना 10 जुलाई रात 8 बजे की है जब युवती अपने दोस्त के साथ अपनी बहन के घर शाहगंज जा रही थी कि उक्त स्थान पर दो बाइक पर सवार छह युवक उसे रोक लिए तथा उसके दोस्त को वहां से भगा दिए तथा युवती को शाहगंज रोड पर कुछ दूर सड़क के किनारे झाड़ी मे ले जाकर सभी छह युवकों ने युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। युवती द्वारा चीखने चिल्लाने पर आरोपी युवको ने जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़िता वहां से किसी तरह अपने घर गयी और दो दिन बाद थाने पहुंचकर आपबीती सुनायी। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म में शामिल अर्पित,ऋषभ और सौरभ एक दूसरे का नाम लेकर बीडियो भी बना रहे थे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उक्त तीन नामजद आरोपी सहित तीन अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 504,506 व अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति अधिनियम 3(2)(वी) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

आईजीआरएस की समीक्षा

जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में आईजीआरएस की समीक्षा की गयी और उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी डिफाल्टर संदर्भ निस्तारण हेतु अवशेष न रहे। 15 जुलाई को पुनः समीक्षा की जाएगी।

सम्पदाकीय कार्यालय

वैशवारा पत्र के प्रधान संपादक रमाकान्त पाण्डेय गोपालपुरी के लिए प्रकाश एवं मुद्रक सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा उमरपुर हरिवन्धनपुर नईगंज जौनपुर से प्रकाशित किया। स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अरूणा प्रेस मेंहनगर आजमगढ़ से प्रकाशित किया।

सम्पादक : सुनील कुमार श्रीवास्तव
मो. 9455322393
सह सम्पादक डा. आदित्य सिंह
मो. 9415893741
जिला संवाददाता : हरिशचन्द्र यादव
मो. 8858583480
कानूनी सलाहकार (एडवोकेट) : सन्तोष कुमार श्रीवास्तव

Email:- vaashvara.123hr@gmail.com
Website:- vaashvara.com

समाचार पत्र में छपी सामग्री के लिए लेख व संवाददाता स्वयं जिम्मेदार होगा पी.आर.वी. के तहत